



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]
No. 121]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2004/ज्येष्ठ 19, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2004/JYAISTHA 19, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2004

अन्तिम जांच परिणाम

विषय : कोरिया गणराज्य, जापान, मलेशिया और चीनी ताइपेई से पॉलिस्टाइरिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा से सम्बन्धित पाटनरोधी जांच।

सं. 14/47/2002-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

1.1 निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ(संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार कोरिया गणराज्य, जापान, मलेशिया और चीनी ताइपेई (जिन्हें आगे सम्बद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पॉलिस्टाइरिन(जिसे आगे सम्बद्ध

वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के सम्बन्ध में दिनांक 14.09.98 की अंतिम जांच परिणाम सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 12/2/97-डीजीएडी में यथाउल्लिखित पॉलिस्टाइरिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू की थी। भारत सरकार ने 17 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 88/98 के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

1.2 प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत सम्बद्ध वस्तु के आयातों के बारे में उपर्युक्त जांच के सम्बन्ध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 10.02.2003 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

1.3 प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (पूर्व में की गई जांच के मद्देनजर जिनके ब्योरे उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

1.4 प्राधिकारी ने भारत में सम्बद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों (पूर्व में की गई जांच के मद्देनजर जिनके ब्योरे उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

1.5 जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए सम्बद्ध वस्तु के आयातों के ब्योरे उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से अनुरोध किया गया था।

1.6 उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार प्राधिकारी ने जांच शुरूआत सम्बन्धी अधिसूचना की एक प्रति ज्ञात निर्यातक तथा सम्बद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध करायी।

1.7 नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने संगत सूचना मांगने के लिए निर्यातकों/उत्पादकों को एक प्रश्नावली भेजी।

1.8 किसी भी ज्ञात निर्यातक/उत्पादक अथवा अन्य निर्यातक/उत्पादक द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

1.9 नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरूआत के बारे में नई दिल्ली स्थित सम्बद्ध देशों के दूतावास को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के सभी सम्बन्धित निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातक को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति सम्बद्ध देशों के दूतावास को भी भेजी गई थी।

1.10 नियम 6(4) के अनुसार सम्बद्ध वस्तु के उन ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को आवश्यक सूचना हेतु प्रश्नावली भेजी गई थी जिनके ब्योरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

1.11 किसी भी आयातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर/सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

1.12 घरेलू उद्योग से क्षति सम्बन्धी सूचना मांगी गई थी जिसका प्रतिनिधित्व मै0 पॉलिस्टाइरिन एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा किया गया था जिसमें सम्बद्ध वस्तु के तीन उत्पादकों अर्थात् मै0 बीएसएफ स्टाइरिन प्रा0 लि0, मै0 एलजी पॉलीमर्स प्रा0 लि0 और मै0 सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स का प्रतिनिधित्व शामिल था। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन लागत/क्षति सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत की गई थी जिसका प्राधिकारी ने विश्लेषण किया था।

1.13 सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उत्पादन की इष्टतम लागत तथा भारत में सम्बद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए घरेलू उद्योग की लागत सम्बन्धी जांच भी की गई थी।

1.14 सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए 31 अक्टूबर, 2003 को अवसर प्रदान किया गया था। अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था। पार्टियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां ले लें और खण्डन, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

1.15 प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा।

1.16 *** से इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पता चलता है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

1.17 विचारित जांच अवधि 01.01.2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक की है।

ख विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

2. वर्तमान जांच में विचारित उत्पाद पॉलिस्टाइरिन है। पॉलिस्टाइरिन वर्सेटाइल थर्मोप्लास्टिक रेजिन है जो सामान्य प्रयोजनी क्रिस्टल और इम्पैक्ट ग्रेडों से लेकर उच्च विशिष्टीकृत रेजिनों तक व्यापक प्रतिपादनों में उपलब्ध है। पॉलिस्टाइरिन के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। तथापि, सामान्य प्रयोजनी पॉलिस्टाइरिन (जीपीपीएस) के रूप में लोकप्रिय क्रिस्टल पॉलिस्टाइरिन तथा हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टाइरिन (एचआईपीएस) के रूप में लोकप्रिय इम्पैक्ट पॉलिस्टाइरिन इस जांच की विषय वस्तु हैं। जीपीपीएस एक सुस्पष्ट, रवाहीन पॉलीमर है जिसका उपयोग खाद्य पैकेजिंग, खाद्य मदों, चिकित्सा उत्पादों तथा ऑडियो कैसेटों, कम्पैक्ट डिस्क तथा अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में

किया जाता है। एचआईपीएस का उपयोग इम्पैक्ट सुधार हेतु पॉलीब्यूटाडाइन इलास्टोमर्स में किया जाता है और इसे खिलोनों, फर्नीचर, घरेलू वस्तुओं, खाद्य पैकेजिंग, फूड सर्विस, चिकित्सा उत्पादों, उपकरणों, भवन सामग्रियों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु पैकेजिंग में उपयोग में लाया जाता है। जीपीपीएस और एचआईपीएस अलग-अलग प्रकार के पॉलिस्टाइरिन हैं और इनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं होता है। सीमाशुल्क उपशीर्ष 39031100 के अंतर्गत वर्गीकृत एक्सपेंसिबल पॉलिस्टाइरिन (ईपीएस के रूप में लोकप्रिय) इस समीक्षा जांच के क्षेत्र में नहीं आती है। पॉलिस्टाइरिन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 39 03 और आईटीसी के 39 03 19 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह विवरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं दिया गया है।

2.1 भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पॉलिस्टाइरिन और सम्बद्ध देशों से निर्यातित पॉलिस्टाइरिन में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और सम्बद्ध देश से आयातित पॉलिस्टाइरिन भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग जैसे समस्त संगत मापदंडों के अनुसार तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता दोनों का उपयोग अदल-बदलकर करते हैं। समान वस्तु के मुद्दे के सम्बन्ध में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया है।

2.2 उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित पॉलिस्टाइरिन वर्तमान याचिका में विचाराधीन वस्तु के समान है और परिणामतः आयातित पॉलिस्टाइरिन तथा घरेलू रूप से उत्पादित पॉलिस्टाइरिन दोनों को पाटनरोधी नियमों के अनुसार सम्बद्ध देशों से आयात की जा रही सम्बद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जाता है।

ग जांच शुरुआत, समीक्षा, आधार एवं घरेलू उद्योग

3. इस मामले में जांच शुरुआत और घरेलू उद्योग के आधार के बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 पॉलिस्टाइरिन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मुम्बई ने सम्बद्ध वस्तु के सभी प्रमुख उत्पादकों को अपना सदस्य बनाया है। अतः प्राधिकारी ये मानते हैं कि मै0 पॉलिस्टाइरिन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मुम्बई पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और वह देश में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करती है।

घ परवर्ती घटनाक्रम

पॉलिस्टाइरिन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इण्डिया) द्वारा किए गए अनुरोध

4.1 हाल के महीनों में पेट्रोलियम की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है जिससे पॉलिस्टाइरिन की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है और प्रयोक्ता उसकी पहुँच से दूर हो गए हैं जिसकी वजह से

कार्बनिक वृद्धि पर अंकुश लग गया है। ऐसी स्थिति में सम्बद्ध देशों से पॉलिस्टाइरिन की आपूर्तियाँ, जिन पर इस समय पाटनरोधी शुल्क भी लगाया जाता है, प्रभावित हुई हैं और उनकी मात्रा में भारी गिरावट आई है। हमें इस बात की जानकारी है कि भारत और अन्य देशों, दोनों स्थानों पर यह सुस्थापित कानून है कि जांच अवधि के आंकड़ों तथा घरेलू बिक्री कीमत के बीच अंतर पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में विचार करना होता है तथा निर्यात कीमत पाटन का निर्णयात्मक परीक्षण होता है। इसके अलावा इस मामले की वास्तविक स्थिति के भीतर पाटनरोधी शुल्क के अभाव में क्षति की पुनरावृत्ति सम्भावित सीमा से अधिक रही है क्योंकि निर्यातक बड़ी स्थापित क्षमताओं, स्थिर घरेलू मांग के बोझ से दब गए हैं तथा पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए जाने से शुल्क के एक बार हटाए जाने की स्थिति में उनकी मात्रा में वृद्धि होने की पूरी-पूरी सम्भावना होगी।

4.2 उपर्युक्त सभी तथ्यों के होते हुए भी भारत के जिम्मेवार निगमित नागरिक के रूप में हम सरकार से यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि वह ऐसा शुल्क लगाए जो आज की स्थिति में बहुत ही कम प्रभाव रखता हो। शुल्क की समाप्ति के बाद ही हम आयात की मात्राओं और कीमतों पर कड़ी नजर रखेंगे और इस मामले में जरूरत के अनुसार आपके तुरंत हस्तक्षेप की मांग करेंगे।

4.3 इस स्थिति में हम मलेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य और ताईवान से आयातित पॉलिस्टाइरिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के आवेदन को एतद्वारा वापस लेते हैं।

निष्कर्ष

5.1 पॉलिस्टाइरिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के आवेदन को वापस लेने का अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए प्राधिकारी सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित पॉलिस्टाइरिन पर 14 सितम्बर, 1998 की अंतिम जांच परिणाम सम्बन्धी अधिसूचना सं० 12/2/1997-डीजीएडी के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथासंस्तुत और 17 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना सं० 88/98-सीमाशुल्क के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करते हैं।

ए. सेनगुप्त, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2004

FINAL FINDINGS

Sub. : Anti-Dumping investigations concerning Sunset Review of anti-dumping duty on imports of Polystyrene from Korea RP, Japan, Malaysia and Chinese Taipei.

No. 14/47/2002-DGAD.—Having regard to the Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A PROCEDURE

The procedure described below has been followed:

1.1 The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules as per Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 initiated Sunset Review to review the need for continued imposition of anti-dumping duty on imports of Polystyrene as indicated in the final findings notification No.12/2/97-DGAD dated 14/9/98 with regards to anti-dumping duty imposed on imports of Polystyrene ((hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Korea RP, Japan, Malaysia and Chinese Taipei ((hereinafter also referred to as subject countries). The Government of India imposed definitive anti dumping duty vide notification no 88/98 Customs dated 17th November 1998.

1.2 The Authority issued a public notice dated 10.2.2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations in respect of the above mentioned investigation concerning imports of the subject goods classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 originating in or exported from subject countries.

1.3 The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were available in view of investigations conducted

earlier) and industry/user associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2).

1.4 The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers ((whose details were available in view of investigations conducted earlier) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).

1.5 Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.

1.6 The Authority provided a copy of the initiation notification to the known exporter and the Embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra.

1.7 The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4):

1.8 No Response/information to the questionnaire was filed by any of known exporters/producers or other exporters/producers:

1.9 The Embassy of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise all concerned exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the known exporter was also sent to the Embassy of the subject countries under rule 6(3).

1.10 A questionnaire was sent to the known importers/user associations of the subject goods whose details were made available by the petitioner for necessary information in accordance with Rule 6(4):-

1.11 No Response/information to the questionnaire was filed by the any of the importers.

1.12 Information regarding injury was sought from domestic industries represented by M/s Polystyrene Association of India representing three producers of the subject goods i.e. M/s BASF styrene Pvt Ltd, M/s LG Polymers Pvt Ltd and M/s Supreme Petrochemicals. The cost of production/injury information was furnished by the domestic industry which was analyzed by the Authority.

1.13 Cost investigation of domestic industries was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner.

1.14 An opportunity was provided to all interested parties to present their views orally on 31st October 2003. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

1.15 The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

1.16 *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

1.17 The period of investigation (POI) considered is 1.1.2002 to 31st December 2002.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

2. The product considered in the present investigations is polystyrene. Polystyrene is a versatile thermoplastic resin available in wide range of formulations from general-purpose crystal and impact grades to highly specialized resins. Polystyrene can be of various forms. However, crystal polystyrene popularly known as General Purpose Polystyrene (GPPS) and impact polystyrene popularly known as High Impact Polystyrene (HIPS) are the subject matter of the present investigation. GPPS is a clear, amorphous polymer and finds application in food packaging, food service items, medical care products, and packaging for audio cassettes, compact discs, and other consumer electronic media. HIPS makes use of polybutadiene elastomers for impact modifications and finds applications in toys, furniture, house wares, food packaging, food service, medical care products, appliances, building materials, consumer electronics, and packaging for electronic media. GPPS and HIPS are different types of polystyrenes and are not substituted with each other. Expandable Polystyrene (popularly known as EPS) classified under custom sub heading 39031100 is beyond the scope of this review investigation. Polystyrene is classified under custom sub-heading 39 03 of Schedule1 of the Customs Tariff Act, 1975 and under 39 03 19 of the ITC. The description is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations. The Authority notes that there are no arguments with regards to the product under consideration by any of the interested parties.

2.1 There is no difference in the Polystyrene produced by the Indian industry and Polystyrene exported from the subject countries. Polystyrene produced by the Indian industry and imported from the subject country is comparable on all relevant parameters such as physical & chemical

characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses. The two are technically and commercially substitutable and consumers have used the two interchangeably. There are no arguments advanced by any of interested parties with regards to the issue of like article.

2.2 In light of the above, the Authority holds that the Polystyrene produced by the Petitioner is identical to the article under consideration in the present Petition and consequently both the imported Polystyrene and domestically produced Polystyrene are considered as "like article" to the subject goods being imported from the subject countries in accordance with the Anti Dumping Rules.

C. INITIATION, REVIEW, STANDING AND DOMESTIC INDUSTRY

3. There are no arguments with regards to the initiation as well as the standing of the domestic industry in this case. The Authority notes that M/s. Polystyrene Producers' Association, Mumbai has got all the major producers of the subject goods as its members and therefore, the Authority holds that M/s. Polystyrene Producers' Association, Mumbai, constitutes domestic industry within the meaning of the rule 2(b) of the Anti Dumping rules having accounted for a major proportion of the production of the subject goods in the country.

D. Subsequent Developments

Submission made by Polystyrene Producers Association (India) on May 24th 2004

4.1 In the recent months, petroleum prices have hit record highs leading to high Polystyrene prices which drive users away thereby curbing organic growth. Give this situation, supplies of polystyrene from the subject countries which are currently also subject to anti-dumping duties, are affected and have sharply come down in volume. We are aware that it is settled law both in India and other countries, data of the Period of Investigation is to be considered, and the difference between the domestic selling price in the ordinary course of trade and the export price is the definitive test for dumping. Further, within the factual matrix of this case, the recurrence of injury in the absence of Anti Dumping Duty is more than likely, as the exporters burdened with large installed capacities, stagnant domestic demand and freed from anti dumping duties will most probably increase their volumes once the duty is lifted.

4.2 Notwithstanding, all of the above, as responsible corporate citizens of India, we do not want our Government to put into place a levy which in today's terms will have little impact. We

will closely track import volumes and prices once the duty lapses and seek your urgent intervention in case required.

4.3 Given this situation, we are hereby withdrawing the application for imposition of Anti-Dumping Duty on Polystyrene imported from Malaysia, Japan, Korea RP and Taiwan.

Conclusions

5.1 On the basis of the submissions made by the domestic industry requesting withdrawal of the application for imposition of Anti dumping duty on Polystyrene , the Authority concludes that there is no justification for the continued imposition of the anti dumping duty and therefore the Authority recommends discontinuance of anti dumping duty on polystyrene originating in or exported from subject countries as recommended by the Designated Authority vide Final Findings notification No. 12/2/1997-DGAD dated 14th September 1998 and imposed by the Central Government vide notification No. 88/98-Customs dated 17th November 1998.

A. SENGUPTA, Addl. Secy. and Designated Authority